National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2026; 1(65): 378-381
© 2026 NJHSR
www.sanskritarticle.com

प्रो. राजू बागलकोट
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
कला संकाय के अधिष्ठाता,
कर्नाटक राज्य अक्कमहादेवी महिला-विश्वविद्यालय, विजयपुर (कर्नाटक)

Correspondence:
प्रो. राजू बागलकोट
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
कला संकाय के अधिष्ठाता,
कर्नाटक राज्य अक्कमहादेवी महिला-विश्वविद्यालय, विजयपुर (कर्नाटक)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 : स्वरूप, उद्देश्य, चुनौतियाँ एवं समकालीन प्रासंगिकता

प्रो. राजू बागलकोट

बीज-शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, समग्र शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, अनुसंधान, डिजिटल शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत।

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक युगांतकारी परिवर्तन का दस्तावेज है। लगभग साढ़े तीन दशकों के बाद प्रस्तुत की गई यह नीति शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन या प्रमाणपत्र प्राप्त करने का माध्यम न मानकर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास का आधार मानती है। इस नीति का मूल उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण, लचीला, बहुविषयक तथा कौशल-आधारित बनाना है, जिससे भारत ज्ञान-आधारित समाज और वैश्विक ज्ञान-महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सके। नई शिक्षा नीति में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, मातृभाषा-आधारित शिक्षण, बहुविषयक अध्ययन, अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, भारतीय ज्ञान-परंपरा तथा नैतिक मूल्यों के समन्वित विकास पर विशेष बल दिया गया है।

यह नीति शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्ति तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व, संवैधानिक आदर्शों, पर्यावरणीय चेतना तथा मानवीय संवेदनाओं से भी जोड़ती है। साथ ही, शिक्षा को अधिक लचीला, विद्यार्थी-केंद्रित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास करती है। यद्यपि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, डिजिटल असमानता तथा संस्थागत समन्वय जैसी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तथापि यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की एक सुदृढ़ आधारशिला सिद्ध होती है। प्रस्तुत आलेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के स्वरूप, उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, चुनौतियों तथा समकालीन प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विवेचन किया गया है। ---

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति का आधार होती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति में ज्ञान, विवेक, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। वैश्वीकरण, सूचना-प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था तथा बदलती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस युग में पारंपरिक शिक्षा

प्रणाली नई चुनौतियों का सामना करने में पर्याप्त नहीं रह गई थी। परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी।

इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की घोषणा की। यह नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992 के संशोधित संस्करण सहित) का स्थान लेती है तथा लगभग 34 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करती है। इस नीति का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि शिक्षा के दर्शन, उद्देश्य, संरचना, पद्धति, मूल्यांकन, अनुसंधान तथा प्रशासनिक ढाँचे में व्यापक परिवर्तन लाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारतीय संविधान की मूल भावना, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), आत्मनिर्भर भारत, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक नागरिकता की अवधारणाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास करती है। यह नीति शिक्षा को समग्र, समावेशी, बहुभाषिक, बहुविषयक, कौशलोन्मुख तथा अनुसंधान-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का स्वरूप व्यापक, समावेशी तथा भविष्य-दृष्टि से परिपूर्ण है। यह नीति शिक्षा को केवल विद्यालय और विश्वविद्यालय तक सीमित न रखकर जीवनपर्यंत सीखने (Lifelong Learning) की प्रक्रिया के रूप में देखती है। इसमें ज्ञान, कौशल, मूल्य, संस्कृति, अनुसंधान तथा नवाचार के समन्वित विकास की परिकल्पना की गई है।

इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 5+3+3+4 शैक्षिक संरचना है, जिसने पूर्व की 10+2 प्रणाली का स्थान लिया है। यह संरचना बालकों के मनोवैज्ञानिक एवं संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) को औपचारिक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाकर शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावी बनाया गया है।

नीति में शिक्षा को रटने की प्रक्रिया से निकालकर अनुभवात्मक, गतिविधि-आधारित, समस्या-समाधान एवं रचनात्मक शिक्षण की ओर उन्मुख किया गया है। साथ ही मूल्यांकन प्रणाली में भी व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों की वास्तविक समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा सृजनात्मकता का मूल्यांकन हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है जो प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्निहित प्रतिभा को विकसित कर सके। नीति में शिक्षा को समावेशी, न्यायसंगत तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विशेष बल दिया गया है ताकि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तक भी समान अवसर पहुँच सकें।

इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य भारत को "वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए अनुसंधान, नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक विश्लेषण, संचार कौशल, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता तथा समस्या-समाधान कौशल विकसित करने पर बल दिया गया है।

नीति शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के साथ-साथ मानवीय मूल्यों, नैतिकता, संवैधानिक दायित्वों, पर्यावरणीय चेतना, लैंगिक समानता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम मानती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की एक महत्वपूर्ण विशेषता बहुविषयक (Multidisciplinary) शिक्षा की अवधारणा है। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान, कला तथा वाणिज्य के बीच जो कठोर विभाजन था, उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अब विद्यार्थी अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा में Academic Bank of Credits (ABC), Multiple Entry and Exit System, चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम तथा अनुसंधान-आधारित अध्ययन जैसी व्यवस्थाएँ विद्यार्थियों को लचीलापन प्रदान करती हैं। इससे शिक्षा अधिक विद्यार्थी-केंद्रित बनती है और सीखने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की एक विशिष्ट उपलब्धि भारतीय ज्ञान-परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है। इसमें भारतीय भाषाओं, दर्शन, साहित्य, योग, आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, कला, संगीत तथा सांस्कृतिक विरासत को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है।

नीति यह स्वीकार करती है कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय परंपरा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। भारतीय ज्ञान-परंपरा का उद्देश्य अतीत का महिमामंडन करना नहीं, बल्कि उसके उपयोगी पक्षों को समकालीन संदर्भों में पुनर्स्थापित करना है। इससे विद्यार्थियों में सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा राष्ट्रीय अस्मिता का विकास होता है।

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

कौशल विकास को अत्यंत महत्व देती है। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय उद्योगों से परिचय, इंटर्नशिप तथा कार्यानुभव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।

उच्च शिक्षा में अनुसंधान संस्कृति विकसित करने के लिए National Research Foundation (NRF) की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा वैश्विक स्तर के शोध वातावरण का निर्माण करना है।

कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल तकनीक शिक्षा का प्रभावी माध्यम बन सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल पुस्तकालय, ई-सामग्री, वर्चुअल प्रयोगशालाएँ तथा तकनीकी नवाचार को विशेष महत्व दिया गया है।

डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है, किंतु इसके साथ अनेक चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का अभाव, डिजिटल उपकरणों की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव तथा डिजिटल विभाजन आज भी गंभीर समस्याएँ हैं। इसलिए नीति तकनीक को शिक्षा का पूरक मानती है, विकल्प नहीं।

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अत्यंत व्यापक एवं दूरदर्शी है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ उपस्थित हैं।

सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है। नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 6 प्रतिशत व्यय करने की अनुशंसा की गई है, किंतु अनेक राज्यों के लिए इसे व्यवहार में लागू करना सरल नहीं है।

दूसरी चुनौती प्रशिक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की उपलब्धता है। नई शिक्षण पद्धतियों, बहुविषयक दृष्टिकोण तथा डिजिटल तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण आवश्यक है।

तीसरी चुनौती डिजिटल असमानता है। आज भी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अनेक विद्यार्थी इंटरनेट, कंप्यूटर तथा स्मार्ट उपकरणों से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में डिजिटल शिक्षा का समान लाभ सभी तक पहुँचाना कठिन है।

चौथी चुनौती राज्यों के बीच समन्वय, संस्थागत स्वायत्तता तथा प्रशासनिक दक्षता से संबंधित है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी सहयोग आवश्यक है।

आज का विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, जैव-प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के युग में प्रवेश कर चुका है। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।

यह नीति केवल रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिकों के निर्माण की परिकल्पना करती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा वैश्विक उत्तरदायित्व से युक्त हों। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तथा मेक इन इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों की सफलता भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निर्भर करती है।

नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला, नवाचारी, उद्यमी तथा सामाजिक रूप से उत्तरदायी नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 निस्संदेह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की संभावनाएँ प्रस्तुत करती है। इसकी बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, मातृभाषा, अनुसंधान तथा भारतीय ज्ञान-परंपरा संबंधी अवधारणाएँ शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और जीवनोपयोगी बनाती हैं।

फिर भी यह आवश्यक है कि नीति के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय विविधताओं, भाषायी बहुलता, सामाजिक असमानताओं तथा संस्थागत आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखा जाए। केवल नीतिगत घोषणाएँ पर्याप्त नहीं होंगी; उनके लिए पर्याप्त आर्थिक निवेश, प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था तथा सतत मूल्यांकन प्रणाली भी आवश्यक है।

अंततः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करने वाली एक दूरदर्शी एवं परिवर्तनकारी नीति है। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, लचीला, बहुविषयक, कौशल-आधारित तथा अनुसंधानोन्मुख बनाना है। यह नीति केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास, नैतिक मूल्यों, रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता तथा रोजगारपरक दक्षताओं के विकास पर भी विशेष बल देती है। भारतीय ज्ञान-परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के माध्यम से यह नीति वैश्विक स्तर पर भारत की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है।

यद्यपि इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की

उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, डिजिटल विभाजन, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव तथा राज्यों के बीच समन्वय जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तथापि इन चुनौतियों का समाधान सुनियोजित नीति-निर्माण, पर्याप्त निवेश, तकनीकी अवसंरचना के विस्तार तथा सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से संभव है। यदि इस नीति को उसके मूल उद्देश्यों के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह न केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पुनरुत्थान करेगी, बल्कि भारत को ज्ञान, नवाचार, अनुसंधान और मानवीय मूल्यों पर आधारित एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 केवल एक शैक्षिक दस्तावेज नहीं, बल्कि इक्कीसवीं सदी के भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्निर्माण का व्यापक घोषणापत्र है।--

फुटनोट

1. भारत सरकार, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020*, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, 2020, पृ. 3– 5
2. वही, पृ. 11– 18
3. वही, पृ. 29– 39
4. वही, पृ. 40– 47
5. वही, पृ. 48– 60

संदर्भ ग्रंथ

1. भारत सरकार. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020*. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, 2020।
2. Ministry of Education. *National Education Policy 2020*. Government of India, New Delhi, 2020.
3. Aggarwal, J. C. *Educational Reforms in India*. New Delhi: Shipra Publications, 2021.
4. Sharma, R. A. *Education in India: Contemporary Issues and Policies*. New Delhi: Atlantic Publishers, 2021.
5. Kumar, Krishna. *Education, Society and National Education Policy 2020*. New Delhi: Sage Publications, 2021.
6. UNESCO. *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO, 2021.